E-mail: justiceambit@gmail.com

E-mail: legalambit.ho@gmail.com

PRGI No: RJBIL/26/A2945

नागौर से प्रकाशित...

जस्टिस एम्बिट

हिन्दी एवं English समाचार पत्र

सत्य | न्याय | अधिकार

पढ़े.... 2

सरोदा थाना...

पढ़े.... 3

डूंगरपुर पुलिस...

वर्षः 01 | डिजीटल अंक | नागौर, गुरुवार 06 अगस्त, 2026 | मूल्यः 2.00 रुपए | पृष्ठः 4

घोटाले में महेश-जोशी सहित 7आरोपियों की जमानत पर सुनवाई पूरी

पूर्व मंत्री ने कहा- शिकायत पर कंपनियों को किया ब्लैक लिस्ट, सरकार बोली- कंपनियां तय करती अधिकारी कौन लगेगा

जयपुर। जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले में तीन महीने से जेल में बंद पूर्व मंत्री महेश जोशी सहित 7 आरोपियों की जमानत याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली की अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री महेश जोशी, तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल सहित अन्य आरोपियों की ओर से कहा गया कि शिकायत मिलने के बाद और एफआईआर दर्ज होने से पहले ही विभाग ने कंपनियों का भुगतान रोकते हुए उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया था। वहीं इसके विरोध में सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने बहस करते हुए कहा- दोनों कंपनियों के प्रोपराइटर पदमचंद जैन और महेश मित्तल पीएचईडी विभाग में अधिकारी तक खुद अपनी मर्जी से लगाते थे। एसीबी में रिकॉर्ड हुए उनके फोन कॉल से पता चलता है कि दोनों को 20 जून 2023 को ही पता था कि मामले की जांच करने के लिए हाईपावर कमेटी किसकी अध्यक्षता में गठित हो रही है। वहीं 4 दिन बाद मंत्री उसी व्यक्ति की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर देते हैं। इससे साफ है कि मामले में कंपनियों को करोड़ों का फायदा पहुंचाने के लिए मंत्री और एसीएस स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं।

महेश जोशी के बेटे की फर्म में राशि ट्रांसफर हुई

सरकार की ओर से कहा गया कि महेश जोशी के करीब संजय बड़ाया के रिश्तेदारों के खातों से करीब 50 लाख रुपए जोशी के बेटे रोहित जोशी की फर्म में ट्रांसफर हुए। पूरे मामले की जांच के लिए हाईपावर कमेटी गठित करने के बाद भी कंपनियों को करीब 14 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। वहीं जब इरकॉन की ओर से आधिकारिक जानकारी आ गई थी कि कंपनियों ने उसके नाम से फर्जी सर्टिफिकेट बनाया है तो फिर किस जांच के लिए हाईपावर कमेटी गठित की गई। वहीं एसीबी की रेड के बाद आनन-फानन में हाईपावर कमेटी ने कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया। जबकि इससे पहले हाईपावर कमेटी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी।

राज्यपाल की मंजूरी से पहले जांच शुरू कर दी

महेश जोशी की ओर से कहा गया कि मुझे गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि ईडी की गिरफ्तारी के बाद सात महीने तक हिरासत में रहने के दौरान एसीबी ने न मुझसे कोई अनुसंधान किया था और न ही गिरफ्तार किया था। एसीबी ने कानूनी रूप से अनिवार्य राज्यपाल की मंजूरी मिलने से पहले ही प्रारंभिक अनुसंधान शुरू कर दिया। एसीबी के पास किसी से भी डिमांड करने का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। फर्जी प्रमाण पत्र का उपयोग महेश जोशी के जलदाय मंत्री और सुबोध अग्रवाल के एसीएस बनने के पहले से ही हो रहा था। विभाग ने जल जीवन मिशन के कुल 140 टेंडर किए थे। इनमें से मंत्री महेश जोशी और एसीएस सुबोध अग्रवाल के कार्यकाल में मात्र चार टेंडर हुए थे।

देश में ऑर्गन डोनेशन में भीलवाडा अव्वल

24 हजार से ज्यादा लोगों ने एक महीने में ली शपथ, आज जयपुर में सम्मान

भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाडा ने डिजिटल ऑर्गन डोनेशन अभियान में देश में पहला स्थान हासिल किया। गुजरात का अहमदाबाद दूसरे नंबर पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर चलाए गए डिजिटल ऑर्गन डोनेशन अभियान को भीलवाडा कलेक्टर जसमीत संधू ने जनआंदोलन बना दिया। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चले अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने शहर से लेकर गांवों तक लगातार जनजागरण किया। टीम ने लोगों से सीधे संवाद कर अंगदान और देहदान का महत्व समझाया। नतीजा, जिले के करीब 24 हजार 400 लोगों ने ऑनलाइन संकल्प पत्र भरकर अंगदान और देहदान के लिए अपनी सहमति दी। जिले की उपलबधि पर 5 अगस्त(बुधवार) को जयपुर में होने वाले समारोह में कलेक्टर जसमीत संधू और सीएमएचओ डॉ. संजीव शर्मा को सम्मानित किया जाएगा।

पीएम की पहल के बाद घर-घर पहुंची टीम

सीएमएचओ डॉ. संजीव शर्मा ने बताया कि यह सम्मान केवल प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग का नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की संवेदनशील सोच का भी सम्मान है, जिन्होंने मृत्यु के बाद भी किसी को जीवन देने का संकल्प लिया। पीएम की पहल पर जिले में एएनएम, आशा कार्यकर्ताओं, बीसीएमओ और मेडिकल टीम ने घर-घर पहुंचकर लोगों को अंगदान(ऑर्गन डोनेशन) के लिए प्रेरित किया और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर किया।

समस्याओं की पोटली लेकर शिक्षामंत्री से मिलने गए शिक्षक

बातचीत विफल, जयपुर में ग्रेड थर्ड टीचर्स का प्रदर्शन; पुलिस ने धरनास्थल से जनरेटर हटाया

जयपुर। तबादला नीति लागू करने की मांग को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों (ग्रेड थर्ड टीचर्स) ने बुधवार को प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने जल्द तबादले शुरू करने, डेपुटेशन नीति में पारदर्शिता लाने और सालों से लंबित मांगों का समाधान करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। इसी बीच, पुलिस ने धरनास्थल से जनरेटर हटा दिया। इसी जनरेटर से प्रदर्शन के दौरान साउंड सिस्टम चलाया जा रहा था। शिक्षकों के बढ़ते विरोध के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बातचीत का न्योता दिया। इसके बाद शिक्षकों का 5 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री से मिलने गया। इस दौरान शिक्षक संघ के संरक्षक सूरजभान सिंह शिक्षकों की समस्याओं की पोटली लेकर निकले। हालांकि शिक्षा मंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल की बातचीत विफल हो गई है। शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे धरना स्थल से नहीं हटेंगे।

ग्रेड थर्ड शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक बोले- सरकार अपने चुनावी वादे से मुकर रही है

ग्रेड थर्ड शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक सुनील महला ने कहा- राजस्थान सरकार अपने चुनावी वादे से मुकर रही है। प्रदेश में 100 दिन में थर्ड ग्रेड शिक्षकों का ट्रांसफर करने का वादा कर सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है और अब तक सरकार शिक्षकों की सुध नहीं ले रही है। उन्होंने कहा- हम हिम्मत नहीं हारेंगे। पहले तो हम सरकार से सिर्फ ट्रांसफर की मांग कर रहे थे, लेकिन अब हम शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का इस्तीफा चाहते हैं। जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी, तब तक हमारा यह धरना जारी रहेगा।

शिक्षकों की समस्याओं की पोटली लेकर शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहा प्रतिनिधिमंडल

शिक्षकों के बढ़ते विरोध के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उन्हें बातचीत का न्योता दिया। इसके बाद शिक्षकों का 5 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री से मिलने उनके घर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान शिक्षक संघ के संरक्षक सूरजभान सिंह शिक्षकों की समस्याओं की पोटली लेकर निकले। उन्होंने कहा- हमारी सबसे पहली मांग शिक्षकों के ट्रांसफर की है। अगर सरकार से इस मांग पर सहमति बनती है, तभी आगे बातचीत होगी।

जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, वे धरना स्थल से नहीं हटेंगे

शिक्षा मंत्री के साथ शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत विफल हो गई है। दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण फिलहाल शिक्षकों का धरना शहीद स्मारक पर जारी रहेगा। शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे धरना स्थल से नहीं हटेंगे।

शिक्षकों की तबादलों पर लगी रोक हटाने की मांग

जयपुर के शहीद स्मारक पर ग्रेड थर्ड शिक्षकों का धरना लगातार जारी है। शिक्षक तबादलों पर लगी रोक को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही, प्रदर्शनकारी शिक्षक अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर भी अड़ गए हैं।

पति-पत्नी की पोस्टिंग अलग-अलग जगह, दादा-दादी के पास रहता है बच्चा

झालावाड़ से प्रदर्शन में शामिल शिक्षक राजेंद्र कुमार नागर ने कहा- मेरी पत्नी भी ग्रेड थर्ड टीचर हैं। हम दोनों की अलग-अलग जगहों पर पोस्टिंग है। इस कारण हमें अपने मासूम बच्चे को दादा-दादी के पास छोड़कर जाना पड़ता है।

गहलोत ने शुभम रेवाड़ को जबरदस्ती पानी पिलाया

पूर्व सीएम बोले- छात्रसंघ चुनाव की मांग बहाल करे सरकार; डोटासरा ने जूस पिलाकर आमरण अनशन तुडवाया

जयपुर। राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने और यूनिवर्सिटी में राजस्थानी भाषा खोलने की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे छात्र नेता शुभम रेवाड़ को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जबरदस्ती पानी पिलाया। शुभम रेवाड़ 14 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। छात्र नेता शुभम एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं। शुभम से मिलने बुधवार को गहलोत मिलने पहुंचे। गहलोत ने अनशन कर रहे शुभम रेवाड़ की बिगड़ती तबीयत पर चिंता जताई। इस दौरान गहलोत ने छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग का समर्थन करते हुए राज्य सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की। गहलोत ने कहा- छात्रसंघ चुनाव बहाल करना छात्रों की पूरी तरह जायज मांग है। सरकार को इसे अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा- छात्र राजनीति लोकतंत्र की पहली पाठशाला होती है और देश के अनेक बड़े नेता छात्रसंघ चुनावों से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचे हैं। वहीं कलेक्टर संदेश नायक शाम को शुभम रेवाड़ से मिलने एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे। कलेक्टर ने बताया- प्रशासन ने विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा विभाग खोलने की मांग को स्वीकार कर लिया है।

कई केंद्रीय मंत्री से लेकर बडे नेता छात्र राजनीति से आगे बढ़े

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- केंद्रीय मंत्री रहे अरुण जेटली से लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़, कांग्रेस के रघु शर्मा, महेश जोशी और मैं खुद छात्र राजनीति से आगे बढ़े हैं। छात्रसंघ चुनाव युवाओं को नेतृत्व विकसित करने का अवसर देते हैं, इसलिए इन्हें बहाल किया जाना चाहिए।

जेन जी आंदोलन के बाद भी सरकार नहीं चेती

अशोक गहलोत ने कहा- देश में हाल ही जेन जी आंदोलन के बाद जो परिस्थितियां बनीं। इसके बावजूद राजस्थान सरकार छात्रों की मांग को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा- छात्र लगातार अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सरकार का रवैया संवेदनशील नहीं दिख रहा। गहलोत ने कहा- 14 दिनों से एक छात्र भूख हड़ताल पर बैठा है और उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। उन्होंने बताया- मुलाकात के दौरान मैंने शुभम रेवाड़ को जबरदस्ती पानी पिलाया, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य स्थिति चिंताजनक होती जा रही है।

मुख्यमंत्री को खुद हस्तक्षेप करना चाहिए

अशोक गहलोत ने कहा- इस मामले में मुख्यमंत्री को खुद हस्तक्षेप कर समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने बताया- इस संबंध में मैंने जयपुर जिला कलेक्टर से भी बातचीत की है। छात्रों की मांग सरकार तक पहुंचाई है। उन्होंने कहा- मैंने शुभम रेवाड़ से भी आग्रह किया है कि अगर सरकार बुधवार शाम तक निर्णय नहीं लेती है।

दिव्यांग बच्चों का प्रदर्शन, बोले- स्कूल में पानी तक नहीं

गहलोत बोले- ऐसे टीचर्स की नियुक्ति, जिन्हें खुद साइन लैंग्वेज नहीं आती; प्रिंसिपल को हटाया, टीचर एपीओ

जयपुर। जयपुर के राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक-बधिर उच्च माध्यमिक स्कूल में आज हंगामा हो गया। दिव्यांग छात्र-छात्राओं ने स्कूल में शौचालयों की बदहाल स्थिति, पानी का संकट और जर्जर भवन की समस्या से परेशान होकर प्रदर्शन किया। मामले की सूचना पर शिक्षा विभाग की टीम, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी स्कूल पहुंचे। गहलोत ने कहा कि बच्चों की समस्या को लेकर मैं खुद सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखूंगा। उन्हें बताऊंगा कि स्कूल में ऐसे टीचर्स की नियुक्ति की गई है, जिन्हें खुद साइन लैंग्वेज नहीं आती है। वहीं हालात भी बद से बदतर है। निरीक्षण में कई खामियां सामने आने के बाद विभाग ने तत्काल प्रिंसिपल को हटा दिया गया। वहीं एक टीचर और एक फोर्थ ग्रेड कर्मचारी को भी APO कर दिया गया।

राजस्थान समान सिविल संहिता-2026 पर ऑनलाइन सुझाव आमंत्रित

http://ucc.rajasthan.gov.in/

नागौर। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित राजस्थान समान सिविल संहिता, 2026 (The Rajasthan Uniform Civil Code, 2026) विधेयक के संबंध में आमजन एवं विभिन्न वर्गों से ऑनलाइन सुझाव एवं अभ्यावेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। राजस्थान के मूल निवासी राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक वेब पोर्टल https://ucc.rajasthan.gov.in अथवा उपलब्ध क्यूआर कोड स्कैन कर अपने सुझाव एवं अभ्यावेदन ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रस्तावित विधेयक के संबंध में निर्धारित अवधि में अधिकाधिक संख्या में अपने सुझाव एवं अभ्यावेदन ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कराएं, ताकि प्राप्त सुझावों पर विचार करते हुए विधेयक को अधिक व्यापक, प्रभावी एवं जनहितकारी बनाया जा सके।

राजस्थान सूचना आयोग ने तहसील हिंडौन के लोक सूचना अधिकारी को लगाई चेतावनी, 21 दिन में सूचना देने के आदेश

हिंडौन सिटी, करौली। राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर ने तहसील हिंडौन से संबंधित एक आरटीआई प्रकरण में महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील कार्यालय हिंडौन को निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर चेतावनी दी है तथा 21 दिनों के भीतर मांगी गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार हिंडौन निवासी राजीव कुमार पुत्र भगवान सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत तहसील परिसर में 15 जुलाई 2025 से 27 अप्रैल 2026 के बीच काटे गए पेड़ों की संख्या, अनुमति, लकड़ी के रख-रखाव, नीलामी तथा जिम्मेदार अधिकारियों के संबंध में जानकारी मांगी थी। समय पर सूचना उपलब्ध नहीं होने पर आवेदक ने राजस्थान राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत की। आयोग ने सुनवाई के बाद पाया कि संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा आयोग के नोटिस का समुचित जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया। आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि भविष्य में आयोग द्वारा जारी नोटिसों का पालन सुनिश्चित किया जाए तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। आयोग ने संबंधित लोक सूचना अधिकारी को आदेश प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर मांगी गई सूचना बिंदुवार, प्रमाणित एवं स्पष्ट रूप से निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश को सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सरकारी विभागों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ग्रामीण सेवा शिविर में खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदनों का हुआ त्वरित निस्तारण

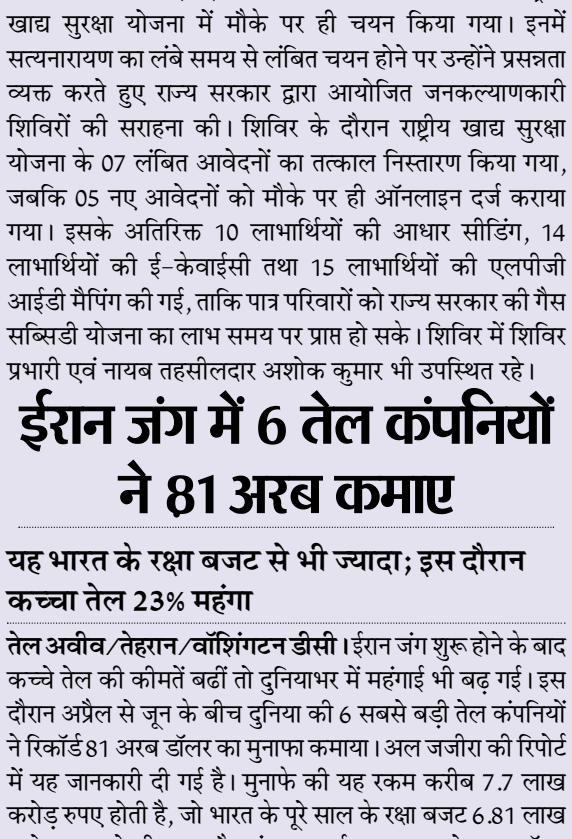

संतोष व्यास@जस्टिस एम्बिट

नागौर। ग्राम पंचायत पांचौड़ी, खींवसर में बुधवार को आयोजित फॉलोअप ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान जिला रसद अधिकारी अंकित पचार के निर्देशन में प्रवर्तन निरीक्षक भंवराराम चौधरी द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित विभिन्न सेवाएं मौके पर ही उपलब्ध कराई गईं। शिविर में 08 पात्र लाभार्थियों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में मौके पर ही चयन किया गया। इनमें सत्यनारायण का लंबे समय से लंबित चयन होने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार द्वारा आयोजित जनकल्याणकारी शिविरों की सराहना की। शिविर के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 07 लंबित आवेदनों का तत्काल निस्तारण किया गया, जबकि 05 नए आवेदनों को मौके पर ही ऑनलाइन दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त 10 लाभार्थियों की आधार सीडिंग, 14 लाभार्थियों की ई-केवाईसी तथा 15 लाभार्थियों की एलपीजी आईडी मैपिंग की गई, ताकि पात्र परिवारों को राज्य सरकार की गैस सब्सिडी योजना का लाभ समय पर प्राप्त हो सके। शिविर में शिविर प्रभारी एवं नायब तहसीलदार अशोक कुमार भी उपस्थित रहे।

ईरान जंग में 6 तेल कंपनियों ने 81 अरब कमाए

यह भारत के रक्षा बजट से भी ज्यादा; इस दौरान कच्चा तेल 23% महंगा

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी। ईरान जंग शुरू होने के बाद कच्चे तेल की कीमतें बढीं तो दुनियाभर में महंगाई भी बढ़ गई। इस दौरान अप्रैल से जून के बीच दुनिया की 6 सबसे बड़ी तेल कंपनियों ने रिकॉर्ड 81 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया। अल जजीरा की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। मुनाफे की यह रकम करीब 7.7 लाख करोड़ रुपए होती है, जो भारत के पूरे साल के रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जंग शुरू हुई तक कच्चा तेल 70 डॉलर प्रति बैरल था। यह अप्रैल से जून के बीच 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया। यानी, तेल कंपनियों ने इस दौरान करीब 23% मुनाफा कमाया। **1. यमन में भारतीय जहाज पर हमला-** यमन के पास लाल सागर में भारतीय झंडे वाले कारोबारी जहाज पर हमला हुआ है। जहाज 'एमएसवी फैजे नूर-ए-औलिया' हमले में डूब गया। सवार सभी 13 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया।

2. ईरान में विदेश मंत्री अब्बास अराघची को हटाने की तैयारी- ईरान के कुछ सांसद विदेश मंत्री अब्बास अराघची के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि अमेरिका से बातचीत और संभावित समझौते ने देश के हितों को नुकसान पहुंचाया है।

देवपुरा स्कूल में 7 कमरे जर्जर घोषित, पीडब्ल्यूडी ने दी बैठने से मनाही

4 साल बाद भी नहीं बने नए कमरे, 392 बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा दांव पर

संतोष व्यास@जस्टिस एम्बिट

डूंगरपुर। जिले के ग्राम पंचायत बिछीवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवपुरा में प्रशासनिक अनदेखी के कारण 392 विद्यार्थियों की पढ़ाई और सुरक्षा पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। स्कूल को सीनियर सेकेंडरी का दर्जा मिले 4 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ नए कक्षा-कक्षों का निर्माण नहीं हो सका है। जर्जर भवनों और मूलभूत सुविधाओं के अभाव से क्षुब्ध होकर ग्रामीणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विद्यालय परिवार ने परिसर का जायजा लिया तथा विद्यालय की जर्जर स्थिति पर चिंता व्यक्त की।

पीडब्ल्यूडी की चेतावनी के बाद बढ़ा संकट

निरीक्षण के दौरान सामने आया कि वर्तमान में विद्यालय के पास कुल 11 कक्षा-कक्ष उपलब्ध हैं। इनमें से 7 कमरे पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की तकनीकी टीम इन 7 कमरों को असुरक्षित घोषित करते हुए इनमें बच्चों को न बैठाने की सख्त हिदायत दे चुकी है। इसके चलते अब केवल 4 कमरों के भरोसे 392 विद्यार्थियों की कक्षाएं संचालित करने की नौबत आ गई है, जिससे अध्यापन कार्य पूरी तरह प्रभावित हो रहा है।

पेजजल और शौचालय का भी अभाव

निरीक्षण दल ने पाया कि भवन के अलावा अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति भी बेहद चिंताजनक है। विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है। बालिकाओं के लिए पृथक और पर्याप्त शौचालय का अभाव है, जिससे छात्राएं सहज महसूस नहीं करतीं। प्रार्थना स्थल पर नुकीले पत्थर निकले हुए हैं, जिससे आए दिन बच्चों के चोटिल होने का खतरा बना रहता है।

सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट गुलाब चंद्र ने कहा कि बच्चों को सुरक्षित माहौल और बुनियादी सुविधाएं देना सरकार व प्रशासन का प्राथमिक कर्तव्य है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों व प्रशासन से नए भवन निर्माण, जर्जर कमरों के स्थान पर सुरक्षित कक्षाओं, शुद्ध पेयजल, बालिका शौचालय और प्रार्थना स्थल के समतलीकरण की मांग की।

इस दौरान एडवोकेट गुलाब चंद्र डोण, माधव लाल मेणात, पंकज भगोरा, अनिल बरंडा, जयंती भगोरा, प्रभुलाल मोलात, मुकेश मोडिया, कांतिलाल बरंडा, हरीश बोड़ात, कमजी बुझ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा।

सरोदा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई; अवैध नीम की लकड़ी से भरा बिना नंबरी ट्रैक्टर व क्रेन जब्त

कराडा के जंगलों से कटाई कर गुजरात ले जाई जा रही थी अवैध लकड़ियाँ

संतोष व्यास@जस्टिस एम्बिट

डूंगरपुर। जिले में हरे वृक्षों की कटाई और अवैध लकड़ी तस्करी पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे %ऑपरेशन पृथ्वी% के तहत सरोदा थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कराडा के जंगलों से अवैध रूप से काटी गई नीम की गीली लकड़ियों से भरा बिना नंबरी ट्रैक्टर-ट्रॉली और लकड़ी लोड करने में इस्तेमाल की जा रही क्रेन को डिटेन किया है। इसके साथ ही मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।

गश्त के दौरान मिली गुप्त सूचना पर कार्रवाई

सरोदा थानाधिकारी मय टीम द्वारा क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कराडा के जंगलों से हरे पेड़ों की अवैध कटाई कर लकड़ियों को परिवहन के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने कराडा के जंगलों में दबिश दी। जाँच के दौरान एक बिना नंबरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अवैध रूप से नीम की गीली लकड़ियों से भरी पाई गई। पास ही लकड़ियों को ट्रैक्टर में लादने के लिए इस्तेमाल की जा रही एक क्रेन भी बरामद हुई।

गुजरात ले जाने की थी योजना, वन विभाग को सौंपा मामला

पुलिस ने मौके से लक्ष्मण पुत्र भुरा कनीपा, निवासी गामडी देवकी थाना सरोदा को डिटेन किया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपित ने खुलासा किया कि इन अवैध लकड़ियों को गुजरात ले जाने की योजना थी। पुलिस ने जब्तशुदा वाहनों व लकड़ी को थाना परिसर में खड़ा करवा दिया है और अग्रिम कानूनी कार्रवाई के लिए वन विभाग सागवाड़ा को सूचित कर दिया गया है। मामले में वन विभाग अग्रिम कार्यवाही करेगा।

मेटा फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने सरकार से माफी मांगी

नई दिल्ली। Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग ने भारत सरकार से चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मैटेरियल , डीपफेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई गलतियों पर माफी मांगी है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से दी है। आज ही संसदीय समिति ने 3 दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने को कहा था। साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो मेटा को भारत में मिलने वाली कानूनी सुरक्षा और कुछ छूट वापस लेने पर विचार किया जा सकता है। इसी मामले में आईटी मंत्रालय और मेटा के अधिकारियों के बीच दो दिन की बैठक चल रही है। सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को दिल्ली बुलाया है। 5 अगस्त को बैठक का पहला दिन था। दरअसल, सरकार पीएम मोदी का वीडियो फेसबुक से हटाने से भी नाराज थी। मोदी ने 23 जुलाई को यह वीडियो पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने पेपर लीक को बड़ी समस्या बताया था। उन्होंने ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी बात कही थी। यह वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक से हटा दिया गया था। बाद में मेटा ने इसे फिर से फेसबुक पर डाल दिया।

प्लास्टिक के नोट अप्रैल-मई 2027 में आएंगे

नई दिल्ली। पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट अगले साल अप्रैल-मई के बीच लॉन्च होंगे। यह जानकारी RBI की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, यानी MPC की तीन दिन चली बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में कम वैल्यू के पॉलीमर करेंसी नोट जारी किए जाएंगे।

मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित न करना आदिवासी समाज की अस्मिता, ऐतिहासिक बलिदान और गौरवशाली परंपरा का अपमान : पूर्व सांसद भगोरा

संतोष व्यास@जस्टिस एम्बिट

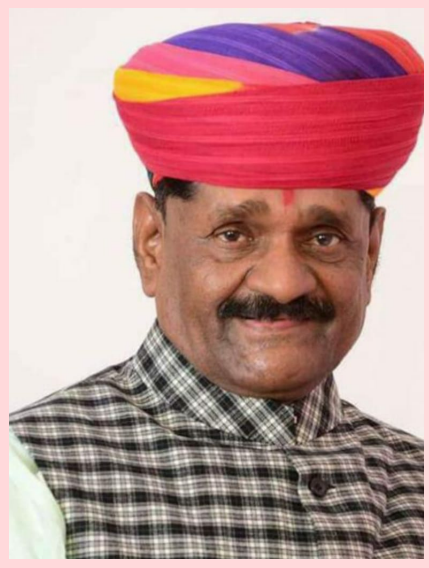

डूंगरपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं बांसवाड़ा-डूंगरपुर के पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा न दिए जाने पर केंद्र सरकार के प्रति कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने इसे आदिवासी समाज की अस्मिता, उनके ऐतिहासिक बलिदान और गौरवशाली परंपरा का सीधा अपमान करार दिया। भगोरा ने कहा कि चुनावों के दौरान आदिवासी वर्ग से बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। पूर्व सांसद ने याद दिलाया कि वर्ष 2022 में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम के अपने दौरे के दौरान इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का आश्वासन दिया था। हालांकि, वर्षों बीत जाने के बाद भी यह वादा अधूरा ही है। उन्होंने कहा कि मानगढ़ धाम केवल एक भौगोलिक स्थल नहीं, बल्कि देश की स्वतंत्रता के लिए आदिवासियों के अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक है।

आदिवासियों का जलियांवाला बाग है मानगढ़

मानगढ़ के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए भगोरा ने कहा कि इसे आदिवासियों का जलियांवाला बाग माना जाता है। 17 नवंबर 1913 को महान समाज सुधारक गोविंद गुरु के नेतृत्व में एकत्रित हुए निष्पाप और शांतिपूर्ण भील आदिवासियों पर ब्रिटिश हुकूमत ने बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाई थीं, जिसमें लगभग 1500 आदिवासी देश के लिए शहीद हो गए थे।

पर्यटन और विकास के अवसरों पर भी लगा ग्रहण

भगोरा ने कहा कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलने से न केवल शहीदों को यथोचित राष्ट्रीय सम्मान मिलता, बल्कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन, बुनियादी ढांचे और रोजगार के नए द्वार भी खुलते। केंद्र सरकार की इस उपेक्षा ने पूरे आदिवासी बहुल क्षेत्र की भावनाओं को आहत किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि वह इस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारते हुए अपनी पूर्व घोषणा पर तत्काल पुनर्विचार करे और जनभावनाओं का सम्मान करते हुए मानगढ़ धाम को अविलंब राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा प्रदान करे।

भासौर में पुलिस की क्लस्टर मीटिंग आयोजित : साइबर ठगी, महिला सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति ग्रामीणों को किया जागरूक

ग्रामीणों ने उठाई रात्रिकालीन गश्त और त्योहारों पर पुलिस बल तैनात करने की मांग

संतोष व्यास@जस्टिस एम्बिट

डूंगरपुर। जिले के ग्राम पंचायत भासौर में बुधवार को सागवाड़ा थाना पुलिस के तत्वावधान में एक विशेष क्लस्टर मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को बढ़ते साइबर अपराधों, महिला एवं बाल सुरक्षा कानूनों तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया।

साइबर ठगी और हनी ट्रैप से सतर्क रहने की अपील

बैठक को संबोधित करते हुए सागवाड़ा थाने के बिट प्रभारी हेड कांस्टेबल नवीन पाटीदार तथा बिट अधिकारी कांस्टेबल योगेश यादव ने वर्तमान में पनप रहे साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी और हनी ट्रैप जैसे गंभीर अपराधों की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से अनजान कॉल, मैसेज या लिंक से सावधान रहने और अपनी गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करने की अपील की।

पोक्सो एक्ट एवं नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर रोक

महिला कांस्टेबल कीर्ति पाटीदार ने महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित कानूनों की जानकारी देते हुए पोक्सो एक्ट के कड़े प्रावधानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने नाबालिग लड़कों व लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। साथ ही, उन्होंने अभिभावकों से विशेष अपील की कि वे अपने कम उम्र के बच्चों को मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से बचाएं, पावर बाइक या तेज रफ्तार वाहन न चलाने दें तथा स्टंटबाजी जैसी खतरनाक आदतों पर रोक लगाएं।

रात्रिकालीन गश्त और त्योहारों पर पुलिस बल तैनात करने की मांग

संवाद के दौरान ग्रामीणों ने गांव में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से रात्रिकालीन पुलिस गश्त बढ़ाने तथा आगामी त्योहारों के दौरान पुलिस की विशेष मौजूदगी सुनिश्चित करने की मांग रखी। इस पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत प्रशासक मानजी परमार, ग्राम विकास अधिकारी दिवेश व्यास, आमजन युवा शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जोशी, बीएलओ शांतिलाल ननोमा, मनोज पंड्या, नानजी पाटीदार, मणीलाल, रमेश पाटीदार, देवीलाल यादव, लक्ष्मीलाल जैन, प्रेमचंद यादव, कचरू यादव, प्रेमशंकर यादव, शकुंतला यादव, नीलम परमार सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

यूपी के बिजनौर में हाईवे पर बह रही गंगा नदी

हिमाचल-उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, 300 सड़कें बंद; झारखंड में बारिश-बिजली गिरने से 14 मौतें

नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश अब जानलेवा साबित हो रही है। झारखंड में मंगलवार को बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा 9 मौतें गिरिडीह, 3 दुमका और 2 लातेहार जिले में हुईं। यूपी के बिजनौर में गंगा नदी का पानी हाईवे पर बह रहा है। हाईवे की अप्रोच रोड नदी के तेज बहाव में बह गई। सड़क पर 12 फीट गहरा गड्ढा हो गया। वहीं, फर्रुखाबाद में बैरिकेडिंग कर हाईवे को बंद करना पड़ा। मिर्जापुर में 3 लोगों की जान चली गई। दो बच्चों की मौत गड्ढे में डूबने से हुई। एक 25 साल के युवक पर बिजली गिर गई। दूसरी ओर केरलम में 1 अगस्त से लगातार बारिश ने अब तक 25 लोगों की जान ले ली है, जबकि 4 लोग लापता हैं। लगातार बारिश और बाढ़ के कारण हजारों लोगों को घर छोड़ने पड़े हैं। केरलम सरकार के मुताबिक, 18 हजार से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड के कारण 300 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। इनमें हिमाचल की 160 और उत्तराखंड की 100 से ज्यादा सड़कें शामिल हैं। उत्तराखंड के देहरादून और बागेश्वर में 12वीं तक के स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई है। असम के शिवसागर जिले के नजीरा सब-डिवीजन में बाढ़ की स्थिति अब ज्यादातर इलाकों में काबू में है। हालांकि, 23 इलाके अब भी प्रभावित हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक, सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। नापालिकुटी इलाके में बड़े पैमाने पर जमीन का कटाव हुआ है। जिला प्रशासन ने बताया कि लगातार बारिश और नगालैंड से आए पानी के कारण कई गांव जलमग्न हो गए थे। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अब राहत और बहाली का काम जारी है। अधिकारियों के मुताबिक, बाढ़ से अब तक 26-27 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4-5 लोग अब भी लापता हैं।

सरकार परिसीमन बिल पर विशेष सत्र बुला सकती है

नई दिल्ली। सरकार परिसीमन पर चर्चा के लिए 16 से 18 अगस्त तक संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को संसद में राहुल, प्रियंका सहित अन्य कांग्रेस सांसदों से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि किरेन रिजिजू ने आज परिसीमन के मुद्दे पर उनसे बात की। हम इस पर विचार करके उन्हें जवाब देंगे। कांग्रेस और विपक्ष का रुख पहले जैसा ही है। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च निकाला। उधर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल राज्यसभा में पास हो गया है। 3 अगस्त को इसे लोकसभा से पास किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक भी संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया था। इस दौरान परिसीमन संशोधन संविधान बिल, संविधान का 131वां संशोधन बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल पर चर्चा की गई थी। 18 अप्रैल को संविधान का 131वां संशोधन बिल पर वोटिंग हुई थी लेकिन सरकार बिल लोकसभा में पास नहीं करा पाई थी। इसके बाद सरकार ने बाकी दो बिल भी पेश नहीं किए थे।

रिजिजू ने परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों से बात की

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज परिसीमन के मुद्दे पर उनसे बात की। हम इस पर विचार करके बाद में उन्हें जवाब देंगे। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस और विपक्ष का रुख पहले जैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले संसद सत्र में पार्टी ने जो रुख अपनाया था, वही अब भी कायम है।

लोकसभा में बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल पास, 135 साल पुराने कानून बदलेंगे

लोकसभा ने बुधवार को बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 को मंजूरी दे दी। यह नया कानून 1891 के ब्रिटिश शासन के समय बने पुराने कानून की जगह लेगा। इस बिल का मकसद यह है कि बैंकों के डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, वर्चुअल और क्लाउड में रखे गए रिकॉर्ड भी अदालत में वैध सबूत (एविडेंस) माने जाएं। लोकसभा में शोर-शराबे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिल पेश किया। हंगामा नहीं थमने पर बिना चर्चा के ध्वनिमत (वॉइस वोट) से बिल पास कर दिया गया।

विधायक गणेश घोघरा ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित न करने को लेकर केंद्र सरकार के हालिया रुख पर जताया कड़ा एतराज

कहा - मानगढ़ धाम पर पीएम मोदी की घोषणा निकला वादा खिलाफी, आदिवासियों के बलिदान का हो रहा अपमान

संतोष व्यास@जस्टिस एम्बिट

डूंगरपुर। जिले के विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा ने बांसवाड़ा जिले के ऐतिहासिक मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित न करने को लेकर केंद्र सरकार के हालिया रुख पर कड़ा एतराज जताया है। हाल ही में संसद में मानगढ़ धाम को लेकर दिए गए केंद्रीय मंत्री के लिखित उत्तर के बाद विधायक घोघरा ने बुधवार को एक वीडियो संदेश जारी कर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है।

संसद के सवाल और मंत्री के जवाब से उपजा विवाद

विधायक गणेश घोघरा ने कहा कि 3 अगस्त 2026 को संसद में सरकार से सवाल पूछा गया था कि क्या राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? इस सवाल के लिखित उत्तर में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पष्ट मना कर दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है और मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया जा सकता।

विधायक ने केंद्र सरकार पर कथनी और करनी में अंतर का लगाया आरोप

घोघरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानगढ़ धाम दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2022 में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी मानगढ़ धाम की पवित्र भूमि पर आए थे और उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की दिशा में काम करने की बात कही थी। लेकिन अब संसद में मंत्री द्वारा दिया गया जवाब यह साबित करता है कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है।

इतिहास और शहादत की उपेक्षा का आरोप

विधायक घोघरा ने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि वर्ष 1913 में संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1500 से अधिक भील आदिवासियों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। अंग्रेजों द्वारा किए गए इस नरसंहार को जलियांवाला बाग से भी बड़ा हत्याकांड माना जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश के इतिहास से आदिवासियों के इस महान बलिदान को मिटाने और किताबों के पन्नों से हटाने का प्रयास कर रही है, जो पूरे देश के आदिवासी समाज का अपमान है।

राष्ट्रव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी

गणेश घोघरा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार और संबंधित मंत्रालय अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करते हैं तथा मानगढ़ धाम को जल्द से जल्द राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं देते हैं, तो आने वाले समय में देश का संपूर्ण आदिवासी समाज एकजुट होकर सड़कों पर उतरेगा और एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करेगा।

डूंगरपुर पुलिस का ऑपरेशन संस्कार, सड़कों पर हुड़दंग मचाने वाले स्टंटबाजों पर कसा शिकंजा, 52 पावर बाइक्स जब्त

संतोष व्यास@जस्टिस एम्बिट

डूंगरपुर। जिले की सड़कों पर तेज रफ्तार से पावर बाइक दौड़ाकर आमजन में भय पैदा करने, खतरनाक स्टंट करने, रील्स बनाने और बिना नंबरी व मॉडिफाइड वाहन चलाकर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले मनचलों के खिलाफ डूंगरपुर पुलिस ने व्यापक स्तर पर शिकंजा कसा है। आमजन की जान-माल की सुरक्षा और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ऑपरेशन संस्कार तथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष धरपकड़ अभियान चलाया गया। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के सख्त निर्देशों पर कुंआ, रामसागड़ा, सागवाड़ा व सदर थाना की पुलिस टीमों ने कार्रवाई करते हुए कुल 52 पावर बाइक्स को जब्त किया है। इस कार्रवाई से सड़कों पर हुड़दंग मचाने वाले तत्वों में हड़कंप मच गया है।

52 पावर बाइक्स की डिटेन

अभियान के तहत कुंआ थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने कुंआ कस्बे में सघन चेकिंग चलाई तथा तेज गति से पावर बाइक चलाकर लोगों को भयभीत करने वाले चालकों पर कार्रवाई करते हुए 12 पावर बाइक्स को जब्त किया गया। वहीं, रामसागड़ा थाना क्षेत्र में रील्स व स्टंटबाजों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर थानाधिकारी के नेतृत्व में अलग-अलग टीमों का गठन किया गया। टीम द्वारा थाना क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने स्टंट करने, रील्स बनाने और तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाने वाले चालकों की 15 पावर बाइक्स डिटेन कीं। जिला मुख्यालय पर सदर थानाधिकारी के नेतृत्व में गठित अलग-अलग टीमों ने सदर थाना क्षेत्र में स्टंट करने, रील बनाने, तेज गति व शराब पीकर लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करते हुए 09 बाइक्स को डिटेन किया। इधर, सागवाड़ा थाना पुलिस ने सागवाडा थाना क्षेत्र में अभियान चलाया। सागवाडा थानाधिकारी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा माही पुल एवं सागवाड़ा शहर में ऑपरेशन संस्कार के तहत कार्रवाई करते हुए 16 पावर बाइक्स को जब्त किया।

एसपी का सख्त संदेश : सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने स्पष्ट किया है कि सड़कों पर आमजन की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी वाहन चालक को बख्शा नहीं जाएगा। बिना दस्तावेज, बिना नंबर प्लेट, तेज रफ्तार व मॉडिफाइड वाहनों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। एसपी ने आमजन और युवाओं से अपील की है कि वे अलग-अलग नामों से ग्रुप बनाकर सड़कों पर भय का माहौल न बनाएं। रील्स बनाने के लिए गाड़ियों के साथ स्टंट कर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में न डालें तथा स्टंट या हथियारों के साथ फोटो-वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड न करें, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने कहा कि पुलिस द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने आमजन से आग्रह किया है कि ऐसे स्टंटबाजों या हुड़दंग मचाने वाले ग्रुप्स की जानकारी डूंगरपुर पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर साझा करें। एसपी ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों और युवाओं को नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने से रोकें।

सहकारिता योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से किसानों को मिले अधिकतम लाभ : कलेक्टर देवेंद्र कुमार

नागौर। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को जिला सहकारी विकास समिति (डीसीडीसी) की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न सहकारिता योजनाओं, पैक्स के डिजिटलीकरण, अधोसंरचना विकास, कृषि सेवाओं के विस्तार तथा बैंकिंग सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की विस्तृत समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने सभी योजनाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारिता व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और किसान हितैषी बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र प्रवर्तित पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना के तहत जिले के स्वीकृत 221 पैक्स में से 171 पैक्स पूर्ण रूप से ई-पैक्स के रूप में ऑनलाइन पोर्टल पर कार्य कर रहे हैं। इससे किसानों को गांव स्तर पर ही पारदर्शी और त्वरित ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं तथा अभिलेखों का सुरक्षित डिजिटलीकरण सुनिश्चित हुआ है। जिला कलेक्टर ने शेष पैक्स को भी शीघ्र ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के अंतर्गत स्वीकृत 500, 250 एवं 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि तीन गोदामों का निर्माण पूर्ण होकर उनका उपयोग भी प्रारंभ हो चुका है। जिला कलेक्टर ने शेष गोदामों का निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए, जिससे किसानों को भंडारण की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। कलेक्टर कुमार ने किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र रियायती दर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित कस्टम हायरिंग सेंटरों की प्रगति की भी समीक्षा करी, जिले की 23 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग सेंटर संचालित हैं तथा बजट घोषणा के तहत छह नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी ऐसे केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। बैठक में बताया गया कि जिले के 170 पैक्स अब कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही स्थान पर 300 से अधिक नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिला कलेक्टर ने इन सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने सहकारिता में सहयोग की भावना को मजबूत करने के लिए जिले की सभी सहकारी समितियों, विशेषकर डेयरी समितियों, के खाते नागौर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में संचालित करने तथा समितियों की समस्त जमा राशि इसी बैंक में रखने के निर्देश दिए। उन्होंने डेयरी सदस्यों के बैंकिंग कार्यों को अधिक सरल बनाने के लिए नाबार्ड के सहयोग से डेयरी समितियों में माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराने की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने बैंक शाखाओं एवं सहकारी समितियों में ग्राहक सुविधाओं को और बेहतर बनाने, गुणवत्तापूर्ण ऋण वितरण, प्रभावी ऋण वसूली, जमा राशि में वृद्धि तथा गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर नियंत्रण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बैंक शाखाओं एवं सहकारी समितियों को विकास कार्यों में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, जिससे जिले की सहकारिता व्यवस्था और अधिक सशक्त एवं परिणाममुखी बन सके। बैठक में नागौर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रतिनिधि, नाबार्ड के अधिकारी, सहकारिता विभाग के अधिकारी तथा विभिन्न सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

दीपके बोले- पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे

छत्रपति संभाजीनगर। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने बुधवार को कहा, 'कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी फिलहाल राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी। अभी भारत को एक मजबूत प्रेशर ग्रुप की जरूरत है, इसलिए कॉकरोच पार्टी उसी भूमिका में काम करेगी। दीपके ने कहा, 'अगर हम राजनीतिक पार्टी बनाते, तो हमारा आंदोलन सफल नहीं होता। आंदोलन इसलिए सफल हुआ, क्योंकि अलग-अलग विचारधाराओं और राजनीतिक दलों के लोग लोकतंत्र को कमजोर करने वाली चीजों के खिलाफ एक साथ आए। आज भारत को किसी नई राजनीतिक पार्टी की नहीं, बल्कि एक मजबूत जन आंदोलन की जरूरत है।' महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में सीजेपी की आज से दो दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। बैठक से पहले मीडिया से बातचीत में दीपके ने बताया कि इसमें जंतर-मंतर आंदोलन की समीक्षा, ई20 पेट्रोल, शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि संगठन को देशभर में कैसे मजबूत किया जाए।

दीपके बोले- झारखंड के प्रदर्शन में जाएंगे, 3 बड़ी बातें

हमारे आंदोलन को सिर्फ शिक्षा के मुद्दे पर समर्थन नहीं मिला। लोगों ने इसलिए साथ दिया, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था, न्यायपालिका, मीडिया और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर उनका भरोसा कम हो गया है। मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था बहुत खराब स्थिति में है और लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा वापस लाने के लिए व्यापक जन आंदोलन और जनता के दबाव की जरूरत है। सीजेपी झारखंड जाएगी और वहां आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ खड़ी रहेगी। हम झारखंड के छात्रों की हर मांग का समर्थन करते हैं। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि छात्र प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस कराने की मांग को लेकर सरकार से बातचीत चल रही है। घायल प्रदर्शनकारियों को कानूनी और मेडिकल मदद देने की भी तैयारी की जा रही है। सौरव ने बताया कि सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक संगठन के मेंटर बने रहेंगे और संगठन समय-समय पर उनसे सलाह लेगा।

सौरव दास का दावा- मीडिया मेरे घर में घुसी, यह प्राइवेसी का उल्लंघन

सौरव दास ने सोशल मीडिया ङ्क पर लिखा- कुछ यूट्यूबर और मीडिया चैनल मेरे घर में घुस आए हैं और घर के अंदर के सीन दिखा रहे हैं। यह न केवल मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन है, बल्कि मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। अगर मेरे घर पर असामाजिक तत्व हमला करते हैं, तो इसके लिए ये यूट्यूबर और उनके वे ट्रोल संचालक सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी ने 20 जून से 25 जुलाई तक, लगातार 36 दिनों तक धरना दिया था। इस दौरान हजारों छात्र, अभिभावक और युवा आंदोलन में शामिल हुए। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी प्रदर्शन में शामिल हुए और भूख हड़ताल पर बैठे। 20 जुलाई को सीजेपी ने संसद मार्च निकाला।

सांसद डॉ रावत ने की रेल मंत्री से मुलाकात, उदयपुर की रेल संबंधी बडी मांगों को रखा, नई रेल सुविधाओं की भी मांग की

वंदे भारत को सूरत तक बढाने, मेवाड को दक्षिण भारत से जोडने की मांग की, एकलिंगपुरा के पास अंडरपास के समुचित सुदृढीकरण की मांग रखी

संतोष व्यास@जस्टिस एम्बिट

उदयपुर/डूंगरपुर। सांसद मन्नालाल रावत ने बुधवार को दिल्ली में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के संसद भवन स्थित कार्यालय मुलाकात कर मेवाड की रेल संबंधी मांगों से अवगत करवाया। डॉ रावत ने उदयपुर से असारवा जाने वाली वंदे भारत को सूरत (गुजरात) तक बढाने, मेवाड को दक्षिणी भारत से विविध ट्रेनों से जोडने, चित्तौडगड से देबारी रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण, उदयपुर से फालना, उदयपुर को सिरोही रोड, उदयपुर से धरियावद होते हुए प्रतापगड को नई रेलवे लाइन से जोडने के साथ ही उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर 2 लाख स्क्वायर मीटर एरिया को शॉपिंग मॉल के रूप में विकसित करने व एकलिंगपुरा के पास अंडरपास के समुचित सुदृडीकरण की मांग रेल मंत्री के समक्ष रखी। रेल मंत्री ने इन मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वान दिया।

सांसद डॉ रावत ने रेल मंत्री को बताया कि उदयपुर से असारवा व असारवा से उदयपुर वन्दे भारत ट्रेन 7 घन्टे से अधिक समय तक असारवा स्टेशन पर खडी रहती है। इसके पूर्ण उपयोग के लिए इसका विस्तार सूरत (गुजरात) तक किया जाना उचित होगा क्योंकि दक्षिण राजस्थान के मेवाड एवं वागड क्षेत्र से लाखों की

संख्या में व्यापारीजन एवं आमजन विविध कार्यों के लिए लगातार सूरत एवं इसके आस-पास के क्षेत्र के लिए यात्रा करते है।

सांसद डॉ रावत ने बताया कि उदयपुर शहर के बालाजी विहार कॉलोनी, एकलिंगपुरा के मार्ग पर पडने वाला रेलवे पुल संख्या 204 (116/9) वर्तमान में छोटा एवं सकडा है, जिसके कारण क्षेत्र के कारण इस मार्ग पर यातायात बाधित रहने, सीवरेज हेतु नाला निर्माण इत्यादि की समस्या का सामना करना पड रहा है। वर्तमान में उदयपुर-उमरडा रेलवे मार्ग के दोहरीकरण का कार्य प्रगतिरत है। यदि इस दोहरीकरण कार्य के साथ ही क्षेत्र में पडने वाले रेलवे पुल संख्या 204 (116/9) की ऊंचाई एवं चौडाई बडाई जाती है, तो क्षेत्रवासियों की उक्त समस्या का समाधान हो सकेगा।

सांसद डॉ. रावत ने रेल मंत्री को बताया कि उदयपुर की देश के दूसरे शहरों से बेहतर रेल कनेक्टिविटी के लिए उदयपुर की जनता द्वारा लगातार मांग की जा रही है। इसके लिए उन्होंने उदयपुर योगनगरी ऋषिकेश ट्रेन (19609/10) जो वर्तमान में सप्ताह में तीन दिन चल रही है, उसे देहरादून तक बडाया जाकर प्रतिदिन चलाये जाने का आग्रह किया। इसी तरह उदयपुर बांदा टर्मिनस ट्रेन (22902/01) जो वर्तमान में सप्ताह में तीन दिन चल रही है. उसे प्रतिदिन चलाने तथा रूट बदलकर वाया अहमदाबाद करने, आगरा आसरवा एक्सप्रेस ट्रेन (01919/20) ट्रेन जो पूर्व में संचालित की गई थी, और यात्रीभार लगभग 100 प्रतिशत था उसे पुन: स्थायी रूप से चलाने की मांग की। सांसद डॉ रावत ने अजमेर-काठगोदाम एक्सप्रेस ट्रेन (रानीखेत एक्सप्रेस 15013/14) को उदयपुर तक बढाने, गुजरात मेल एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 12901/02) जो ट्रेन प्रतिदिन मुम्बई-अहमदाबाद-मुम्बई के बीच संचालित है, प्रात: 05.50 बजे मुम्बई से अमहदाबाद पहुंचने के पश्चात् रात 22.50 बजे मुम्बई के लिए प्रस्थान करती है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर लगभग 17 घण्टे इसका ठहराव रहता है इसलिए इस ट्रेन का उदयपुर तक विस्तार करने की मांग की।

सांसद डॉ रावत ने हाल ही में रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन परिसर की लगभग 19,588 वर्गमीटर भूमि को 99 वर्ष की दीर्घकालीन लीज पर व्यवसायिक एवं आवासीय गतिविधियों के लिए देने का भी विरोध किया व इसे रोकने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर नए रेल ट्रैक के विकास, यार्ड मेंटेनेंस सुविधाओं, वॉशिंग एरिया तथा अन्य परिचालन आवश्यकताओं के लिए उक्त अतिरिक्त भूमि की नितांत आवश्यकता रहेगी।

बॉम्बे हाईकोर्ट बोला- गडकरी से जुडी आपत्तिजनक पोस्ट फौरन हटाएं

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और एक्स को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट फौरन हटाने का आदेश दिया। साथ ही पोस्ट करने वाले यूजर्स की जानकारी भी मांगी। हाईकोर्ट ने इन कंपनियों से कहा, 'भविष्य में भी अगर मंत्री की ओर से ऐसा कोई कंटेंट ध्यान में लाया जाता है, तो उसे भी हटाया जाएगा। गडकरी ने 27 जुलाई को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि सोशल मीडिया पर उन्हें और उनके परिवार को ई-20 इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से होने वाले कथित मुनाफे से जोड़ा जा रहा है। याचिका में कहा गया, लोग उनके खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट्स और मीम बना रहे हैं। इससे उनकी इमेज खराब हो रही है। सुनवाई के दौरान मेटा (फेसबुक और इंस्टाग्राम) और एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) के वकील कोर्ट में मौजूद रहे।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- ऐसे मामलों के लिए सिस्टम बनाना चाहिए

जस्टिस आरिफ डॉक्टर की सिंगल बेंच ने कहा, मेटा और गूगल फौरन इन पोस्ट को हटाने पर काम करे। यह भी पूछा कि क्या उनके पास ऐसा कोई सिस्टम है, जिससे बिना कोर्ट गए ऐसी पोस्ट को हटाया जा सके। प्लेटफॉर्म को ऐसी पोस्ट खुद ही हटा देनी चाहिए। जस्टिस डॉक्टर ने कहा, %आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, तो क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, जो ऐसे मामलों को पकड़ सके। अगर कोई अश्लील या अपमानजनक चीज डालता है, तो उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। यह बहुत ही घटिया बात है। हाईकोर्ट ने गडकरी को मेटा और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ-साथ उन अज्ञात लोगों के खिलाफ भी सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दी है, जो उनके और उनके परिवार के खिलाफ गलत जानकारी फैला रहे हैं।

मोदी की सलाह- सोशल मीडिया इस्तेमाल में सावधानी बरतें

बीजेपी में शामिल हुए सांसदों से कहा, संसद में चिल्लाने या गुस्से में बोलने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने आवास पर बीजेपी के करीब 37 नवनिर्वाचित और अन्य दलों से आए राज्यसभा सांसदों के साथ नाश्ते पर चर्चा की। इनमें आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेता भी मौजूद थे। पीएम ने सांसदों को आगाह किया कि सांसद फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहें लेकिन सतर्क रहें। संसदीय बहस के दौरान चिल्लाने या गुस्से में बोलने की जरूरत नहीं है। हर मुद्दे पर अपनी बात शांति से रखें।

सद में गरिमा और संयम जरूरी

संसदीय बहस के दौरान होने वाली तनातनी पर पीएम ने कहा कि सदन के अंदर की चिंता को बाहर न ले जाएं। उन्होंने कहा कि सदन का माहौल कभी-कभी तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन आपको इसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। पीएम ने सांसदों को सलाह दी कि वे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों को जानें। आपको पता होना चाहिए कि सदन में आपके साथी कौन हैं। उन्होंने सांसदों को संसद की लाइब्रेरी में हर दिन कम से कम एक या दो घंटे बिताने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

योग और समय प्रबंधन का मंत्र

जब सांसदों ने पीएम से उनके व्यस्त शेड्यूल और जिम्मेदारियों को संभालने का राज पूछा, तो उन्होंने कहा, मैं वर्तमान में जीता हूं। अभी मैं आप सभी से बात कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ यहीं हूं। उन्होंने सांसदों को सलाह दी कि वे वर्तमान में रहें और देश के बेहतर भविष्य के लिए काम करें।

पिछले 5 महीने में दाल 8रुपए, तेल 6रुपए महंगा हुआ:दूध-चीनी समेत राशन की 99% चीजों के दाम बढे

मुंबई। 28 फरवरी से 3 अगस्त तक, यानी पिछले 5 महीनों में आम आदमी के खाने-पीने का खर्च तेजी से बढ़ा है। 28 फरवरी वही दिन है, जब अमेरिका-ईरान-इजराइल में जंग शुरू हुई थी। उपभोक्ता मामले विभाग के प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम के मुताबिक इन 5 महीनों में 16 मुख्य खाद्य वस्तुओं में से 15 के दाम बढ़े हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा तेजी दालों और तेल में रही। इसके अलावा चना दाल 4.65 प्रति किलो, अरहर दाल 5.96, उड़द 5.71, चीनी 2.25, मूंग दाल 4.55 प्रति किलो और दूध 3, सरसों तेल 7.56 प्रगति लीटर महंगा हुआ। चावल के दाम 1.57 और नमक के 0.85 प्रति किलो बढ़े, जबकि आटे की कीमतों में 0.22 की मामूली बढ़ोतरी हुई है। चीनी के दाम बढ़ने के पीछे एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने की लगातार ऊंची मांग और चीनी उत्पादन में अपेक्षाकृत कमी को प्रमुख कारण माना जा रहा है।

आर्टिकल 370 हटने के 7 साल, जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बढी

अमरनाथ यात्रा रोकी गई, बिना परमिशन रैली-धरने पर रोक; विपक्ष आज ब्लैक डे मना रहा

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के आज सात साल पूरे हो गए। इस मौके पर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर, कुलगाम, पहलगाम समेत संवेदनशील इलाकों में मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू है। जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षाबलों के काफिलों की आवाजाही रोक दी गई है। वहीं, जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा भी एक दिन के लिए रोक दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक, एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। CRPF ने रामबन में जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सर्च ऑपरेशन चलाया, जबकि कुलगाम पुलिस ने एनएच-44 पर गाड़ियों और लोगों की आईडी की जांच तेज कर दी है। बिना परमिशन रैली और धरने पर रोक लगाई गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी समेत कई राजनीतिक दल आज ब्लैक डे मना रहे हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को कैंडल मार्च निकाला और लोगों से विरोध दर्ज करने की अपील की। विपक्ष आर्टिकल 370 हटाने के फैसले का विरोध करते हुए जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहा है।

एससी बोला- युवाओं की बात सुनना सबसे ताकतवर हथियार

भटके युवक पत्थरबाजी करते हैं, सरकार आक्रामक रवैये से बचे; सीजेपी प्रदर्शन में हिंसा का मामला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में हिंसा को लेकर एक याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि युवाओं की बात सुनना सबसे ताकतवर हथियार है। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को संयम रखना चाहिए। अगर कुछ भटके हुए युवक पत्थरबाजी भी करें, तब भी उन्हें समझाने और शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार को भी आक्रामक रवैया अपनाने से बचना चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन की बेंच ने यह टिप्पणी रिटायर्ड एयरफोर्स अफसर मनीष कुमार सोलंकी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका में 20 जुलाई के संसद चलो मार्च के आयोजकों यानी सीजेपी प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कोर्ट ने इस याचिका को इसी मामले से जुड़ी दूसरी याचिका के साथ जोड़ दिया। सीजेपी के समर्थकों ने 20 जुलाई को संसद तक मार्च निकालने की कोशिश की थी। इस दौरान पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया था। सीजेपी के समर्थकों ने 20 जुलाई को संसद तक मार्च निकालने की कोशिश की थी। इस दौरान पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया था।

सुप्रीम कोर्ट बोला- युवाओं को काउंसलिंग मिलनी चाहिए, 4 टिप्पणी

1. भटके युवाओं को समझाने की जरूरत: चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर कुछ भटके हुए युवक पत्थरबाजी करते हैं, तब भी उन्हें समझाने और सलाह देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उन्हें काउंसलिंग मिलनी चाहिए। अगर सरकार आक्रामक रवैया अपनाएगी, तो हालात और बिगड़ सकते हैं और हिंसा बढ़ सकती है। इससे बचना चाहिए।

2. पुलिस संयम रखे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बढ़ावा दे: सीजेआई ने कहा कि सबसे जरूरी बात शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बढ़ावा देना है। अगर कोई घटना हो भी जाती है, तो पुलिस को बहुत संयम से काम लेना चाहिए, ताकि हालात नियंत्रण से बाहर न जाएं। जहां भी ऐसी घटनाएं हों, वहां बहुत सावधानी से स्थिति संभालनी चाहिए।

3. युवाओं को हिंसा की राह पर जाने से रोकना होगा: सीजेआई ने कहा कि बहुत सोच-समझकर कदम उठाने होंगे, ताकि युवा हिंसा की राह पर न जाएं। सबसे अच्छा तरीका है उन्हें समझाना और शांत करना। उनकी बात सुनिए और समझिए कि वे आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं।

4. कानून-व्यवस्था एजेंसियों के विवेक पर छोड़ें: अंत में सीजेआई ने कहा कि ऐसे मामलों से कैसे निपटना है, यह कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर छोड़ देना चाहिए। उन्हें ऐसी परिस्थितियों से निपटने का अनुभव हमसे और आपसे ज्यादा है।

याचिकाकर्ता ने कहा- सरकार को झुकना नहीं चाहिए, 4 दलीलें

1. 15 दिन बाद भी आयोजकों पर कार्रवाई नहीं: याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील रिजवान अहमद ने कहा कि दिल्ली में 20 जुलाई को हुई घटना के 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आयोजकों की जवाबदेही तय नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आयोजक लगातार टीवी चैनलों पर जाकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं और माहौल शांत करने की कोशिश नहीं कर रहे।

2. सरकार प्रदर्शनकारियों के आगे न झुके: वकील ने राजस्थान की हालिया कानून-व्यवस्था की घटना का हवाला देते हुए कहा कि सरकार को प्रदर्शनकारियों के आगे नहीं झुकना चाहिए। उन्होंने कहा- राजस्थान में एक युवक की मौत हो चुकी है। अगर दिल्ली में सरकार झुकती है, तो यह दूसरी जगहों पर भी उदाहरण बनेगा। कल लखनऊ में कॉलेज के छात्र भी मांगों को लेकर बसों पर पत्थर फेंकेंगे, तो क्या वहां की सरकार भी झुक जाएगी?

3. पत्थरबाजी करने वालों को छोड़ना खतरनाक होगा: वकील ने कहा कि पत्थरबाजी करने वालों को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि सरकार दबाव में है। उन्होंने कहा- यह बहुत खतरनाक उदाहरण होगा। तीन साल पहले किसान सिंघु बॉर्डर पर थे। कल जनरेशन अल्फा, बीटा या दूसरी पीढ़ियां भी इसी तरह आंदोलन करेंगी।

4. संसद लोकतंत्र का मंदिर, जवाबदेही तय हो: वकील ने कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है। अगर 500 लोग संसद परिसर में घुस जाते, तो कौन जानता है कि उनके पास देसी कट्टा या कोई हथियार नहीं होता? अगर वे गोली चला देते तो क्या होता? उन्होंने कहा कि वे किसी हाईवे या रेलवे ट्रैक पर नहीं जा रहे थे, बल्कि लोकतंत्र के मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। इसलिए सभी की जवाबदेही तय होनी चाहिए।